RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 15 APRIL TO 21 APRIL 2020 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 34 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

लॉकडाउन के बीच समय की परवाह किये बिना 'तेल सेवक' समुद्र के बीच तेल एवं गैस क्षेत्रों में कर रहे काम
Page 2

ग्राहकों को बुकिंग के पैसे नहीं लौटाएंगी एयरलाइंस
Page 4

कोरोना वायरस महामारी के चलते यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री मार्च में 51 प्रतिशत गिरी : सियाम
Page 7

editoria!

कोरोना और आर्थिक गतिविधि

शुक्र है कि तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक और उसके सहयोगियों के बीच तेल उत्पादन में कटौती को लेकर समझौते पर सहमति बन गई है। वरना आने वाले दिनों में इनमें से कुछेक दिवालिया हो जाते और इस संकट के दौर में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाती। महामारी के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की मांग में आई कमी को देखते हुए इसकी कीमत स्थिर रखने के लिए उत्पादन में 10 फीसदी कटौती का फैसला लिया गया है। मेक्सिको के अड़े रहने से इस समझौते में देरी हुई हालांकि बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उसको भी कटौती के लिए राजी कर लिया। महामारी का असर दिखने से पहले ही सऊदी अरब और रूस में तेल कीमतों को लेकर विवाद चल रहा था और रूस को सबक सिखाने के लिए सऊदी अरब ने अपना प्रॉडक्शन बढ़ा दिया था। इसके पहले चीन-अमेरिका ट्रेड वॉर ने वर्ल्ड इकनॉमी का बाजा बजा रखा था। अभी ज्यादातर देशों में लॉकडाउन है। आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हैं। शुरू में सारी सरकारों को लगा कि वायरस का हमला थोड़े समय की बात है। इसका असर कम होते ही सब कुछ पटरी पर लौट आएगा। ऐसी गलतफहमियों के लिए अब कोई गुंजाइश नहीं बची है। निकट भविष्य में कोविड-19 का प्रकोप खत्म होने की संभावना नहीं दिख रही। ऐसे में सारे देशों का रुख यही है कि आर्थिक गतिविधियां बीमारी से जूझने के क्रम में ही शुरू कर दी जाएं वरना आने वाले दिनों में एक बड़ी आबादी के सामने भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। अमेरिका मई में लॉकडाउन हटाने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप इस चुनावी साल में अपनी अर्थव्यवस्था को जल्दी पटरी पर लाना चाहते हैं। चीन में कई कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है, हालांकि संक्रमण के नए मामलों ने वहां एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस बीच जापान ने अपनी कुछ कंपनियों को चीन से बाहर शिफ्ट करने का फैसला किया है और उनके लिए एक पैकेज घोषित करने वाला है। भारत ने भी तय कर लिया है कि एक तरफ कोविड-19 के खिलाफ मोर्चा खोले रखा जाए, दूसरी तरफ सावधानी बरतते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं ताकि लोगों के हाथ में नकदी पहुंचे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और उद्योग संगठनों से बातचीत के बाद एक एग्जिट प्लान तैयार किया है। प्रस्ताव है कि सड़क बनाने और आवश्यक वस्तुओं के निर्माण से जुड़े उद्योगों को पहले चरण में उत्पादन शुरू करने की इजाजत दी जाए। कुछ जरूरी सेवाओं की अनुमति मिले, जैसे ठेले पर सब्जी और फलों की बिक्री। फ्रिज, टीवी, एसी रिपेयर करने वालों, धोबी, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन के काम पर से रोक हटाने का भी प्रस्ताव है। किसानों को कई छूटें पहले से मिली हुई हैं। कटाई के लिए उन्हें और सहूलियतें दी जाएंगी। उम्मीद करें कि इससे बीमारी को सीमित रखने में कोई अड़चन नहीं पेश आएगी और आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी।

कोरोना वायरस महामारी से वैश्विक इकॉनमी में गिरावट का भरपूर फायदा उठा रहा चीन

अब सस्ते तेल पर नजर

नई दिल्ली। एजेंसी

एक तरफ जहां पूरी दुनिया खुद को महामारी से बचाने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन दुनियाभर में ताबड़तोड़ निवेश करने में लगा है। महामारी से शेयर बाजार और कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट का वह हर संभव फायदा उठा रहा है। इन दिनों कच्चा तेल सस्ता होने की वजह से वह तेल का विशाल भंडार बनाने में लग गया है। इसके अलावा, शेयर बाजारों में आई गिरावट से दुनियाभर की कंपनियों के शेयर अपने निचले स्तर पर चले गए हैं, जिसका भी चीन भरपूर फायदा उठा रहा है। सस्ती कीमतों पर शेयर खरीदकर वह एशिया के बड़े देशों की कंपनियों में ताबड़तोड़ हिस्सेदारी ले रहा है।

निचले स्तर पर तेल की कीमतें

कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनियाभर में लॉकडाउन के कारण कच्चे तेल की मांग में भारी गिरावट आने तथा रूस के साथ प्राइस वार की वजह से सऊदी अरब द्वारा बाजार में आपूर्ति बढ़ाने से पिछले महीने यूएस ऑइल फ्यूचर और ब्रेंट क्रूड की कीमतें 18 साल के निचले स्तर पर चली गईं।

चीन के लिए जबर्दस्त मौका

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दाइवा कैपिटल मार्केट्स में चीन एवं हॉन्गकॉन्ग एनर्जी रिसर्च के हेड डेनिस आईपी ने कहा कि हालांकि ओपेक तथा रूस द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करने की उम्मीद से कीमतों को थोड़ा बल मिला, लेकिन फिर भी दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह भंडार को जितना भर सकता है, उतना भरने का जबर्दस्त मौका है।

रेकॉर्ड 72% तेल आयात

चीन की अर्थव्यवस्था जैसे-जैसे फैली उसकी विदेशी तेल पर निर्भरता बढ़ती गई। पिछले साल उसने अपने कुल इस्तेमाल का 72% तेल आयात किया था, जो एक रेकॉर्ड है। विदेशी तेल आपूर्ति पर बढ़ती निर्भरता की वजह से पेइचिंग उन तरीकों पर फोकस कर रहा है, जिससे वह ऊर्जा की बढ़ता मांग को रोक सके। सरकारी तेल कंपनियों में उत्पादन बढ़ाने के अलावा, अपने तेल के रिजर्व को बढ़ाने को लेकर उसने इसपर वर्षों काम किया है। सीएनपीसी के मुताबिक, पिछले साल चीन ने 19.1 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन किया था, जो उसके सालाना खपत का 30% है।

तेल रिजर्व अमेरिका के बराबर करने के करीब

चीन के तेल रिजर्व के लिए यह साल बेहद अहम होने जा रहा है। साल 2020 के अंत तक चीन अपने इमर्जेंसी भंडार में 8.5 करोड़ टन तेल चाहता है, जो अमेरिका द्वारा अपने स्ट्रैटिजिक पेट्रोलियम रिजर्व में रखे जाने वाले तेल के बराबर होगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा तेल बैकअप है।

HDFC के 1.75 Cr शेयर खरीदे

पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउजिंग लोन देने वाली देश की दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए हैं। शेयर बाजार से मिले आंकड़ों के मुताबिक, चीन के केंद्रीय बैंक ने एचडीएफसी लिमिटेड के 1,74,92,909 शेयर खरीदे हैं, जो कंपनी की एक फीसदी हिस्सेदारी है।

रणनीतिक तेल भंडार को भरने के लिये आईओसी को यूएई से मिली पहली खेप

नयी दिल्ली। एजेंसी

भारत ने वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव में इस समय भारी गिरावट का फायदा उठाते हुए तेल का रणनीतिक तेल-भंडार भरने की पहल की है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से 10 लाख बैरल कच्चे तेल की पहली खेप मंगलूरू पहुंच गयी है। देश में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति अथवा उनके दाम में किसी भी तरह की बाधा आने अथवा उठापटक होने जैसी स्थिति से निपटने के लिये इन रणनीतिक भंडारों को तैयार किया गया है। तेल कंपनियों से कहा गया है कि वह विश्व बाजार में सस्ते दाम पर उपलब्ध कच्चे तेल की खरीद कर इन रणनीतिक भंडारों को भर दें। कर्नाटक के मंगलूरू और पादुर तथा आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिये इन रणनीतिक भंडारों को तैयार किया गया है। इंडियन आयल के निदेशक (मानव संसाधन) रंजन कुमार माहपात्रा ने ट्वीट कर कहा, "पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिशानिर्देश के तहत इंडियन आयल कच्चे तेल का आयात कर रहा है। सस्ते कच्चे तेल के मौजूदा परिदृश्य का लाभ उठाते हुये इस आयात से भारत के पेट्रोलियम के रणनीतिक आरक्षित भंडार को मजबूत किया जा रहा है। ऐसा 10 लाख बैरल कच्चा तेल मंगलूरू पहुंच चुका है और उसे सुरक्षित भंडार सुविधा में पहुंचाया जा रहा है।" इस साल जनवरी के बाद से विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम में 60 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है।

लॉकडाउन के बीच समय की परवाह किये बिना 'तेल सेवक' समुद्र के बीच तेल एवं गैस क्षेत्रों में कर रहे काम

नयी दिल्ली। अपने घरे से मीलों दूर गहरे समुद्र के ऊपर लोहे के खंबों पर खड़े एक ढांचे पर समय की परवाह किये बिना 'तेल सेवक' लगातार देश के सबसे बड़े तेल एवं गैस क्षेत्रों का परिचालन कर रहे हैं। समुद्र के बीचों बीच ऐसी जगह जहां रात- दिन रहकर काम करना काफी मुश्किल होता हैं वहां ओएनजीसी के करीब 4,500 कर्मचारी और अधिकारी अपनी 14 दिन की तय ड्यूटी से आगे बढ़कर 35- 35 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। यह तेल सेवक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी स्थित तेल के कुंओं को लगातार चालू रखे हुये हैं। इतने शारीरिक और मानसिक तनाव देने वाले इस काम के लिए इन्हें यदि कोई बात एक सूत्र में पिरोती है तो वह है देश की ऊर्जा जरूरत को पूरा करने का जज्बा।

कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव को रोकने लिए लागू किए गए लॉकडाउन (बंद) की वजह से सभी लोग इन दिनों अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। पहले देश में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए यह पाबंदी लगाई गई जिसे अब बढ़ाकर तीन मई तक कर दिया गया है। इसके बावजूद नौ महिलाओं समेत यह कर्मचारी लगातार इन तेल मंचों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके

स्थान पर आने नये कम्रचारी वहां नहीं पहुंच पाये हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शशि शंकर ने मीडिया से कहा, " मुझे इन कर्मचारियों की ओर से संदेश प्राप्त हुआ है कि देश की जरूरत के लिए जब तक आवश्यकता होगी वह समुद्र बीच स्थित इन तेल मंचों पर काम करते रहेंगे। उन्हें इससे खुशी मिलती है।" देश के अधिकतर तेल एवं गैस क्षेत्र समुद्री क्षेत्र में ही हैं। इन जगहों से तेल निकालने के लिए ओएनजीसी जैसी कंपनियों को समुद्र तल के भीतर खुदाई करनी होती है और वहां समुद्र में ही तेल कुंए के ऊपर लोहे का ढांचा खड़ा करना होता है। बाद में निकलने वाले तेल को पाइपों के जरिये किनारे तक पहुंचा दिया जाता है। इन लोहे के ढांचों पर ही क्षेत्र का परिचालन और रखरखाव करने वाले कर्मचारियों के लिए रहने की सुविधा होती है।

अरब सागर में मुंबई हाई ओएनजीसी का सबसे प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके अलावा बासेन और हीरा जबकि पश्चिम बंगाल में कृष्णा गोदावरी बेसिन तेल क्षेत्र हैं। वैश्विक स्तर पर ऐसे क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को महीने में 14 दिन समुद्र के बीच में काम करना होता है और बाकी का समय वह घर पर अपने परिवार के साथ बिताते हैं। शंकर ने कहा कि ओएनजीसी के अधिकतर कर्मचारी इसी 14 दिन के चक्र में काम करते हैं। लेकिन सार्वजनिक पाबंदी की वजह से उनके बदले काम करने वाले कर्मचारी मुंबई नहीं पहुंच सके। मुंबई से ही इन कर्मचारियों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से समुद्र के बीच स्थित तेल क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है।

मथुरा रिफाइनरी ने कोलतार की आपूर्ति फिर शुरू की

मथुरा। एजेंसी

देशव्यापी लॉकडाउन (सार्वजनिक पाबंदी) के बीच मथुरा रिफाइनरी ने देश के विभिन्न इलाकों में कोलतार (बिटुमन) की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए आवागमन पर सार्वजनिक पाबंदी लागू की है।मथुरा रिफाइनरी के कार्यकारी निदेशक अरविंद कुमार ने यहां रविवार को संवाददाताओं से कहा, 'रिफाइनरी से 100 ट्रक कोलतार रवाना किया गया है।''सार्वजनिक पाबंदी के दौरान अब तक पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति की जा रही थी तथा कोलतार की आपूर्ति रुकी हुई थी। कुमारने कहा रिफाइनरी में 24 घंटे काम चालू है तो कोलतार का स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए इसकी आपूर्ति करना जरूरी हो गया था।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन को भरोसे में लेने के बाद इनकी आपूर्ति शुरू की गयी है।कुमार ने कहा कि कोलतार की आपूर्ति करने वाले ट्रक ड्राइवरों को मास्क, सैनेटाइजर और खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं ताकि रास्ते में उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े।कुमार ने कहा कि तीन हफ्ते की सार्वजनिक पाबंदी के दौरान जहां डीजल और पेट्रोल की मांग में कमी आयी है। वहीं एलपीजी सिलेंडरों की मांग बढ़ी है।

ट्रकों को चलने, औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति से पेट्रोल, डीजल की मांग बढ़ेगी

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

पेट्रोल और डीजल की मांग में माह के दूसरे पखवाड़े में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने 20 अप्रैल के बाद ट्रकों को चलाने और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और उद्योगों को कामकाज की अनुमति दे दी है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' (बंद) के कारण पेट्रोल और डीजल की मांग में काफी गिरावट आयी है। देशव्यापी बंद के कारण कारखानों में कामकाज ठप होने, सड़क एवं रेल परिवहन बंद होने तथा उड़ानें निलंबित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री 66 प्रतिशत से अधिक कम हुई है जबकि विमान ईंधन की खपत में 90 प्रतिशत की बड़ी गिरावट आयी है। उद्योग से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, "सरकार ने राज्यों के बीच एवं राज्यों के भीतर सड़कों एवं रेल से माल ढुलाई की अनुमति दे दी है। साथ ही खेती-बाड़ी के साथ नगर निगम की सीमा से बाहर उद्योगों को काम करने की अनुमति 20 अप्रैल से दे दी है। इन सभी से ईंधन की खपत बढ़ेगी।''ट्रक डीजल के बड़े उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं। इसके अलावा फसलों की कटाई तथ खेती संबंधी अन्य कार्यों में डीजल का उपयोग होता है। कुछ मालगाड़ियां भी डीजल से चलती हैं। इन सभी गतिविधियों से माह में 20 अप्रैल से डीजल की मांग बढ़ेगी। इसके अलवा ई-वाणिज्य परिचालकों को वाहन चलाने की अनुमति दी गयी हैं। ये वाहन ज्यादातर पेट्रोल का उपयोग करते हैं। अधिकारी ने कहा, "विमान ईंधन को लेकर कोई उम्मीद नहीं है लेकिन अगर सरकार 20 अप्रैल से सभी उद्योगों और गतिविधियों को मंजूरी देती है, पेट्रोल और डीजल की मांग निश्चित रूप से बढ़ेगी।" सरकार ने अबतक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। उसने कहा कि इसके अलावा सड़क निर्माण और औद्योगिक संकुलों में परियोजनाओं पर काम शुरू करने की अनुमति दी गयी है। इससे भी ईंधन की खपत बढ़ेगी। दुनिया के सबसे बड़े बंद से धीरे-धीरे बाहर निकलने तथा अटकी पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के

लिये सरकार ने बुधवार को सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों, किसानों तथा उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में 20 अप्रैल के बाद कामकाज शुरू करने की अनुमति दे दी है। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिये बंद की अवधि तीन मई तक के लिये बढ़ा दी थी। इससे पहले, 25 मार्च से 21 दिन के बंद की घोषणा की गयी थी। सरकार 20 अप्रैल से ई-वाणिज्य कंपनियों, सड़कों, बंदरगाहों तथा हवाई जहाजों के जरिये माल की ढुलाई पर लगी पाबंदी हटा लेगी। इसके अलवा नगर निगम सीमा से बाहर स्थिति खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनन, पैकेजिंग सामग्री, तेल एवं गैस खोज एवं रिफाइनरियों को काम करने की अनुमति होगी। सड़क निर्माण, सिंचाई परियोजनाओं, निर्माण कार्य तथा सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) तथा निर्यात उन्मुख इकाइयों में परियोजनाओं पर काम करने की छूट होगी। देशव्यापी बंद के कारण मांग लगभग मंद पड़ने से ईंधन की बिक्री मार्च में एक दशक से भी अधिक समय के न्यूनतम स्तर पर आ गयी। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत इस साल मार्च में 17.79 प्रतिशत घटकर 1.608 करोड़ टन रही।बंद के दौरान डीजल की मांग 24.23 प्रतिशत घटकर 56.5 लाख टन रही। इसी प्रकार, पेट्रोल की बिक्री 16.37 प्रतिशत घटकर मार्च में 21.5 लाख टन पर आ गयी। वहीं विमान ईंधन की मांग 32.4 प्रतिशत घटकर 4,84,000 टन पर पहुंच गयी। एकमात्र रसोई गैस ईंधन एलपीजी की मांग इस दौरान बढ़ी। एलपीजी की बिक्री मार्च में 1.9 प्रतिशत बढ़कर 23 लाख टन रही।

तेल उत्पादन में कटौती को लेकर समझौते के बाद तेल के दाम में नरमी

सिंगापुर। उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में मंगलवार को वैश्विक बाजारों में तेल के भाव में गिरावट आ गई। कारोबारियों ने इस खबर को तवज्जो नहीं दी कि कच्चे तेल के उत्पादक सप्ताहांत उत्पादन में कटौती पर सहमत हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से कच्चे तेल के वायदा भाव में तेजी आयी थी। उन्होंने सोमवार को संकेत दिया कि तेल उत्पादक देश उत्पादन में दो करोड़ बैरल प्रतिदिन तक कटौती करने पर विचार कर रहे हैं। यह मात्रा इससे पहले सार्वजनिक रूप से घोषित आंकड़े के मुकाबले दोगुनी है। इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली। हालांकि, भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे (11.00 जीएमटी) जून महीने में डिलिवरी के लिये यूरोपीय मानक लंदन ब्रेंट नार्थ सी तेल का भाव 0.4 प्रतिशत गिरकर 31.61 डॉलर प्रति बैरल रह गया।इसी प्रकार, अमेरिकी मानक वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड का भाव मई डिलिवरी के लिये 1.7 प्रतिशत घटकर 22.04 डॉलर प्रति बैरल रहा।सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले सहयोगी तेल उत्पादक देशों ने रविवार को मई से उत्पादन में करीब एक करोड़ बैरल प्रतिदिन की कटौती के लिए एक समझौता किया था। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर में जारी लॉकडाउन के चलते कच्चे तेल की मांग में भारी कमी आई है और ऐसे में कीमतें तेजी से गिरी हैं। इसके अलावा सऊदी अरब और रूस के बीच कीमत युद्ध ने इस संकट को बढ़ा दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्पादन में कटौती से कीमतों पर दबाव कम तो होगा, लेकिन यह मांग की स्थिति पर निर्भर करेगा।

सऊदी अरब ने कहा

कुल तेल कटौती 1.95 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान

रियाद। एजेंसी

सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि ओपेक (तेल निर्यातक देशों का संगठन) और उसके सहयोगी देशों के तेल उत्पादन में कटौती के संकल्प के साथ जी-20 के अन्य देशों में कमी तथा रणनीतिक भंडारों के लिये होने वाली खरीद से प्रतिदिन 1.95 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार से हट सकता है।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि तेल उत्पादक देश उत्पादन में दो करोड़ बैरल प्रतिदिन तक कटौती

करने पर विचार कर रहे हैं, यह मात्रा इससे पहले सार्वजनिक रूप से घोषित 97 लाख बैरल प्रतिदिन के आंकड़े के मुकाबले दोगुनी है। ट्रंप ने संवाददाता सममेलन में कहा, ''लोग एक करोड़ बैरल प्रतिदिन कटौती की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि यह आकड़ा करीब 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन हो सकता है।''हालांकि, उन्होंने कोई ब्योरा नहीं दिया लेकिन सऊदी अरब ने इस संदर्भ में पूरा विवरण दिया है।

सऊदी अरब के नेतृत्व वाले ओपेक और रूस के नेतृत्व वाले गैर-ओपेक तेल उत्पादक देशों ने रविवार को अगले दो महीनों में उत्पादन में 97 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने के लिए एक समझौता किया था। इस पहल का मकसद कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' (बंद) तथा सऊदी अरब और रूस के बीच कीमत युद्ध के कारण कच्चे तेल के भाव में आयी गिरावट का रोकना था।सऊदी मीडिया ने मंगलवार को ऊर्जा मंत्री युवराज अब्दुल अजीज बिन सलमान के हवाले से कहा कि आपेक एवं उसके सहयोगी देशों के अलावा जी-20 उत्पादक देशों ने 37 लाख टन कटौती का संकल्प जताया है।इसके अलावा विभिन्न देश मई और जून में रणनीतिक तेल भंडार के लिये तेल खरीदेंगे। इससे कुल प्रभाव 1.95 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक हो सकता है।युवराज अब्दुल अजीज ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो सऊदी अरब उत्पादन में अपने कोटा 85 लाख बैरल प्रतिदिन से कम कटौती करेगा।

कोविड- 19

माल, सेवा अनुबंध रद्द होने पर जीएसटी रिफंड के लिये दावा कर सकते हैं कारोबारी

नयी दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने विमानन और होटल क्षेत्र को उन मामलों में जीएसटी वापस लेने की अनुमति दी है जहां बिल बनाये गये लेकिन बाद में अनुबंध रद्द कर दिया गया। एयरलाइन और होटल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बुकिंग रद्द होने को ध्यान में रखते हुये बोर्ड ने यह कदम उठाया है।सीबीआईसी ने करदाताओं को कोरोना वायरस संकट के कारण अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए कुछ स्पष्टीकरण जारी किया है।उन मामलों के बारे में में जहां सेवा देने के एवज में अग्रिम तौर पर राशि ली गयी है और बिल काटे गये लेकिन बाद में वे रद्द हो गये, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने स्पष्ट करते हुए कहा, ''ऐसे मामले जहां आउटपुट देनदारी नहीं है और जिसके एवज में क्रेडिट नोट को समायोजित किया जा सकता है, ऐसे मामलों में पंजीकृत व्यक्ति दावा करने के लिये आगे आ सकता है। कर का अतिरिक्त भुगतान यदि कोई है तो उसका दावा फार्म जीएसटी आरएफडी-01 के जरिये किया जा सकता है।'' इसी प्रकार, उन मामलों में जहां वस्तुओं की आपूर्ति की गयी और उसके लिये कर के साथ बिल सृजित हुए लेकिन बाद में खरीदार ने संबंधित वस्तु को लौटा दिया, इस बारे में बोर्ड का कहना है जहां उत्पादन देनदारी नहीं है जिसके एवज में 'क्रेडिट नोट' समायोजित किया जा सके, वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता कर वापसी के लिये दावा कर सकता है। उसके लिये भी जीएसटी आरएफडी-01 फार्म भरना होगा।

सीबीआईसी ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय जारी किया है जब विमानन और होटल क्षेत्रों में कोरोना वायरस महामारी और उसकी रोकथाम के लिये जारी 'लॉकडाउन' के कारण बड़े पैमाने पर 'बुकिंग' रद्द हो रही हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा, ''इस स्पष्टीकरण से उन क्षेत्रों को राहत मिलेगी जो मौजूदा संकट से सर्वाधिक प्रभावित हैं और वे सरकार से कर वापसी के लिये दावा कर सकेंगे...।''साथ ही सीबीआईसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्यातक 2020-21 के लिये 30 जून तक हलफनामा जमा कर सकते हैं जबकि पहले यह समयसीमा मार्च अंत तक थी। माल वं सेवा कर (जीएसटी) के तहत निर्यातकों को बिना एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) भुगतान किये केवल हलफनामा देकर निर्यात करने की अनुमति दी जाती है।

ट्रक ड्राइवर निकलने को तैयार नहीं, कहीं होने न लगे आटा-दाल की किल्लत?

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोनावायरस की वजह से हुए देशव्यापी लॉकडाउन में अब आटा, चावल, दाल, खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की किल्लत शुरू हो गई है। खुदरा दुकानदार जहां थोक दुकानदारों पर कम सामान भेजने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं थोक दुकानदारों का कहना है कि सामान ढोने के लिए ट्रक नहीं मिल रहे हैं। ट्रक वालों से पता चला है कि उन्हें ड्राइवरों की घोर तंगी हो रही है, क्योंकि उनके अधिकतर ड्राइवर गांव चले गए हैं। ऐसे माहौल में या तो वे खुद नहीं लौटना चाहते या फिर उनके परिवार वाले नहीं लौटने दे रहे हैं। इस वजह से आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त परिवहन नहीं हो पा रहा है।

कोरोना वायरसः अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को कच्चे तेल की मांग में रिकॉर्ड गिरावट की आशंका

पेरिस। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को कोरोना वायरस के कारण इस साल कच्चे तेल की वैश्विक मांग में रिकॉर्ड गिरावट आने की आशंका है। एजेंसी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। एजेंसी ने अपनी हालिया मासिक रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये दुनिया भर में सरकारें लॉकडाउन (बंद) कर रही हैं। इसके कारण इस साल कच्चे तेल की वैश्विक मांग में रिकॉर्ड गिरावट आ सकती है। एजेंसी ने कहा कि अप्रैल में कच्चे तेल की वैश्विक दैनिक मांग में 2.9 करोड़ बैरल की गिरावट देखने को मिल सकती है। यह 1995 के बाद का निचला स्तर होगा। पूरे साल के दौरान दैनिक मांग में 93 लाख बैरल की गिरावट रह सकती है। हालांकि एजेंसी ने कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति पर लगाम लगाने के उपायों तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के प्रयासों से इस साल की दूसरी छमाही में तेल बाजार में क्रमिक सुधार होने लगेगा।

पेट्रोल पंपों के संगठन ने तीन तेल वितपणन कंपनियों से वित्तीय पैकेज की मांग की

चेन्नई। एजेंसी

देश में खुदरा ईंधन बिक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पेट्रोलियम डीलरों के समूह सीआईपीडी ने रविवार को सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों तेल विपणन कंपनियों...इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल...कारोबार में बने रहने के लिये प्रोत्साहन पैकेज की मांग की। सीआईपीडी कंसोर्टियम ऑफ इंडियन पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष एम नारायण प्रसाद ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये जो एहतियाती कदम केंद्र एवं राज्य सरकारों ने उठाये हैं, उससे पेट्रोल पंपों के पास नकदी की तंगी हो गयी है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों को चलाने के लिये लागत और खर्च बना हुआ है लेकिन रोजाना जो पैसा आता था, उसमें कमी आयी है। इससे कर्मचारियों का वेतन, बिजली दर आदि के लिये धन की 90 प्रतिशत की कमी पड़ रही है। प्रसाद ने तेल विपणन कंपनियों को लिखे पत्र में कहा, '...दैनिक स्तर पर डीलर मार्जिन संग्रह में जो कमी आयी है, उसे पूरा करने की जरूरत है।''

कमजोर आर्थिक परिदृश्य के बीच शेयर बाजारों ने शुरुआती लाभ गंवाया, सेंसेक्स 310 अंक टूटा

मुंबई। कोविड-19 की वजह से कमजोर आर्थिक परिदृश्य के बीच शेयर बाजारों ने बुधवार को शुरुआती लाभ गंवा दिया। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच स्थानीय बाजार नुकसान में बंद हुए। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज और कोटक बैंक जैसे प्रमुख शेयरों में नुकसान से सेंसेक्स 310 अंक टूट गया। कारोबारियों ने कहा कि कमजोर वैश्विक रुख के अलावा डॉलर के मुकाबले रुपया अपने सर्वकालिक निचले स्तर पर बंद हुआ, जिससे यहां धारणा प्रभावित हुई।बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स दिन में कारोबार के दौरान 1,346 अंक के दायरे में ऊपर-नीचे होने के बाद अंत में 310.21 अंक या 1.01 प्रतिशत के नुकसान से 30,379.81 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊपर में 31,568.36 और नीचे में 30,222.07 अंक तक गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 68.55 अंक या 0.76 प्रतिशत के नुकसान से 8,925.30 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में कोटक बैंक का शेयर सबसे अधिक 6.23 प्रतिशत टूटा। हीरो मोटोकॉर्प में 4.83 प्रतिशत, बजाज फाइनेंस में 4.63 प्रतिशत, एचडीएफसी में 3.61 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक में 3.57 प्रतिशत और मारुति सुजुकी में 3.55 प्रतिशत का नुकसान रहा। वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचसीएल टेक, आईटीसी और नेस्ले के शेयर 6.07 प्रतिशत तक चढ़ गए। कारोबारियों ने कहा कि आज बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला। लेकिन बेहद उतार-चढ़ाव भरे कारोबार ने इसने अपना शुरुआती लाभ गंवा दिया। वैश्विक बाजारों के नकारात्मक रुख तथा आर्थिक वृद्धि में भारी गिरावट के अनुमान से यहां धारणा प्रभावित हुई। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने मंगलार को 2020 के लिए भारत की वृद्धि की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 1.9 प्रतिशत कर दिया है। जनवरी में आईएमएफ ने भारत की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था। इसके अलावा माना जा रहा है कि 1930 के दशक की महामंदी के बाद वैश्विक अब अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस की मार से सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है। इस बीच, सरकार ने बुधवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक 20 अप्रैल से कामकाज कर सकेंगी, बशर्ते वे सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। हालांकि सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन पर तीन मई तक तक रोक रहेगी। एमके हेल्थ मैनेजमेंट के शोध प्रमुख जोसफ थॉमस ने कहा, ''बाजार भागीदारों के लिए स्थिति राज्य सरकारों द्वारा लॉकडाउन में सीमित ढील के ब्योरों के बाद अधिक स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि, अभी बाजार में उतार-चढ़ाव बना रहेगा, क्योंकि वृद्धि और मूल्य स्तर को लेकर स्थिति अनिश्चित है।'' जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''बंद की वजह से लगभग सभी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। बाजार पिछली तिमाही के नतीजों के बजाय भविष्य के वित्तीय आकलन पर अधिक ध्यान देगा। इससे कुछ शेयर विशेष उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।'' उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनियों के तिमाही नतीजों की शुरुआत होगगी। ऐसे में निवेशक जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से उनकी सेवाएं कितनी प्रभावित हुई हैं। व्यापक बाजार रुख के उलट बीएसई मिडकैप और स्मॉल कैप में 1.32 प्रतिशत तक का लाभ रहा। अंतर बैंक विदेशी विनिमय बाजार में बुधवार को रुपया 17 पैसे टूटकर अपने सर्वकालिक निचले स्तर 76.44 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ। ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 4.43 प्रतिशत के नुकसान से 28.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, हांगकांग का हैंगसेंग और जापान का निक्की नुकसान में रहे। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार भी नीचे चल रहे थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 377 पर पहुंच गई है। वहीं 11,439 लोग इससे संक्रमित हैं। वैश्विक स्तर पर इस महामारी से 1.2 लाख लोगों की जान जा चुकी है। वहीं करीब 19 लाख लोग इससे संक्रमित हैं।

मारीशस श्रेणी-I एफपीआई के तहत पात्र देश के रूप में अधिसूचित

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की पहली श्रेणी के तहत मारीशस को पात्र देश के रूप में अधिसूचित किया है। इससे मारीशस की निवेश इकाइयां हल्की फुल्की अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) जरूरतों को पूरा करते हुये भी भारत में पहली श्रेणी एफपीआई के तौर पर काम कर सकेंगी। श्रेणी-I एफपीआई में सरकार तथा केंद्रीय बैंक, सरकारी संपत्ति कोष अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन या एजेंसियां शामिल हैं जो सरकार से संबद्ध हों। इसमें वे इकाइयां भी शामिल हैं जिसमें सरकार या सरकार से संबंधित निवेशकों का कम-से-कम 75 प्रतिशत सीधे या परोक्ष रूप से नियंत्रण हो। वित्त मंत्रालय ने एक आदेश में कहा, ''केंद्र सरकार मारीशस को सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) नियमन 2019 के नियमन 5 (ए) (iv) के उद्देश्य से पात्र देश अधिसूचित करती है।'' नियमन के तहत यहां तक कि उस अनियमित कोष को भी अनुमति होगी जिसका निवेश प्रबंधक नियमित है और श्रेणी-I एफपीआई के तहत अधिसूचित है। लेकिन इसके लिये शर्त है कि निवेश प्रबंधक अनियमित इकाइयों के सभी कार्यों (भूल-चूक) की जिम्मेदारी ले।

ग्राहकों को बुकिंग के पैसे नहीं लौटाएंगी एयरलाइंस

मुंबई। एजेंसी

घरेलू विमानन कंपनियों ने देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद एक बार फिर यह तय किया है कि वह यात्रा टिकट रद्द करने पर ग्राहकों को रकम नहीं लौटाएंगी, बल्कि इसके एवज में उन्हें बिना अतिरिक्त शुल्क के नई तिथियों पर बुकिंग की सुविधा देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले लगाई गई 21 दिन की पाबंदी 14 अप्रैल को खत्म हो गई।

नई तिथि पर यात्रा की सुविधा की पेशकश

वाणिज्यिक उड़ानों पर रोक जारी

सार्वजनिक बंदी की वजह से देश में वाणिज्यिक यात्री विमानन सेवाओं पर भी रोक जारी है। विमानन कंपनियों ने 25 मार्च से 14 अप्रैल की अवधि के लिए बुक किए गए टिकटों की राशि लौटाने के बजाय ग्राहकों को बदली तिथियों पर टिकट बुक करने की सुविधा दी थी। हालांकि, एयर इंडिया को छोड़कर अधिकतर विमानन कंपनियों ने 14 अप्रैल के बाद की अवधि के लिए घरेलू उड़ानों की बुकिंग जारी रखी थी।

डीजीसीए ने की घोषणा

प्रधानमंत्री की मंगलवार की घोषणा के बाद नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों का परिचालन भी तीन मई तक बंद रहने की अधिसूचना जारी कर दी। डीजीसीए ने कहा, 'नागर विमानन मंत्रालय से मिले आदेश के अनुसार देश में तीन मई 2020 तक सभी तरह की उड़ानों का परिचालन बंद रहेगा।'

कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा

विस्तारा विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, 'हम सार्वजनिक पाबंदी बढ़ने की अवधि से प्रभावित टिकटों की बुकिंग रद्द करने की प्रक्रिया में हैं। हम ग्राहकों को 31 दिसंबर, 2020 तक नए तारीखों पर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट बुक करने की सुविधा देंगे।' हालांकि, एयरलाइन ने कहा है कि नई बुकिंग पर यात्रा किराये में यदि कोई अंतर आता है तो वह ग्राहक को देना होगा।

नई तारीखों पर टिकट बुकिंग

गोएयर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ऐसी स्थिति के लिए पहले से तैयार है। उसने सोमवार को ही अपनी 'प्रोटेक्ट योर पीएनआर' योजना को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था। कंपनी अपनी इस शुल्क मुक्त नई तारीखों पर टिकट बुक करने की योजना की समीक्षा बाद में करेगी। विमानन परामर्श कंपनी 'सेंटर फॉर एशिया-पैसेफिक एविएशन' (सीएपीए) ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक पाबंदी पर किसी तरह की स्पष्टता के अभाव में टिकटों की बिक्री को 'ग्राहकों के साथ अनुचित' व्यवहार बताया था। सीएपीए ने कहा कि इससे पहले किंगफिशर और जेट एयरवेज का परिचालन बंद होने से ग्राहकों को टिकट का पैसा वापस नहीं हो सका और उन्हें करोड़ों का चूना पहले ही लग चुका है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष की 25 गरीब देशों को कर्ज से राहत देने की मंजूरी

वाशिंगटन। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने सोमवार को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अभियान में मदद के लिये 25 गरीब देशों को तत्काल कर्ज राहत उपलब्ध कराने की घोषणा की है।आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जियोर्जिवा ने एक बयान में कहा कि मुद्राकोष ने गरीब सदस्य देशों को संकट के समय में उनके कर्ज दायित्वों से राहत देने का निर्णय किया है। यह राहत फिलहाल छह महीने के लिये दी जा रही है। इससे उन्हें अपने दुर्लभ संसाधनों का आपात चिकित्सा और अन्य राहत कार्यों में उपयोग करने में मदद मिलेगी।मुद्राकोष के निदेशक मंडल ने कर्ज राहत को मंजूरी दे दी है। जिन देशों को मदद दी जा रही, उनमें ज्यादातर अफ्रीकी देश हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान, यमन, नेपाल और हैती भी इस सूची में शामिल हैं।कर्ज राहत का वित्त पोषण आईएमएफ के आपदा नियंत्रण और राहत ट्रस्ट (सीसीआरटी) के तहत किया जाएगा। इस न्यास की स्थापना पश्चिम अफ्रीका में 2015 मे एबोला महामारी से निपटने के लिये किया गया था। अब कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिये गरीब सदस्य देशों को मदद दी जा रही है।फिलहाल इस ट्रस्ट के पास 50 करोड़ डॉलर है। जापान, ब्रिटेन, चीन ओर नीदरलेंड इसके मुख्य योगदानकर्ता हैं। जियोर्जिवा ने कहा, ''मैं दानदाताओं से ट्रस्ट को संसाधनों से भरने के लिये आग्रह करती हूं ताकि हम अपने गरीब सदस्य देशों को पूरे दो साल के लिये कर्ज भुगतान से राहत उपलब्ध करा सके।'

कोरोना वायरसः

पाबंदियों के दूसरे चरण में कृषि, सहायक गतिविधियों की अनुमति

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू सार्वजनिक प्रतिबंधों के दूसरे चरण में कृषि तथा डेयरी, मछली पालन के कार्यों के साथ साथ चाय, कॉफी और रबर के बागानों में सावधानियां बरतते हुए काम काज चलाने की अनुमति दी गयी है। बगानों में श्रमिकों की ज्यादा से ज्यादा आधी संख्या के साथ काम चलाने को कहा गया है। इस बाबत सरकार ने बुधवार को दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देश में चाय, कॉफी और रबड़ बागानों को मजदूरों की आधी संख्या के साथ काम करने की अनुमति है ताकि कार्यस्थल पर व्यक्तियों के बीच सुरक्षित अंतर बना रहे। काजू के प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन का काम भी अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिकों के साथ करने की अनुमति दी गई है। गृह मंत्रालय ने, ''तीन मई तक बढ़ायी गयी सार्वजनिक रोक के दूसरे चरण में लागू करने के लिए दिशानिर्देशों के नये स्वरूप'' को जारी करते हुए कहा, कृषि और बागवानी के सभी कार्यों को करने की पूरी छूट हैं। कोरोना लॉकडाऊन (प्रतिबंधों) के दौरान सरकार ने खेती-बाड़ी और खेत-मजदूरों के काम चालू करने की अनुमति दी है। इस दौरान एमएसपी (कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने) कार्यक्रम संबंधी कामकाज सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों को भी काम करने की छूट दी गयी है। यहां तक कि कृषि मंडी समितियों द्वारा संचालित मंडियों या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और साथ ही राज्य सरकार या उद्योग द्वारा सीधे किसानों या किसान उत्पादक संगठनों द्वारा सीधे अनाज खरीद कार्य संचालित करने की अनुमति है। सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे ग्रामीण स्तर पर विपणन और कृषि वस्तुओं की खरीद के काम को विकेंद्रीकृत करने को बढ़ावा दें। गेहूं जैसे रबी की फसलों की कटाई चल रही है, इसलिए सरकार ने कटाई और बुआई से संबंधित मशीनों और अन्य कृषि और बागवानी उपकरणों के राज्य के भीतर किसी स्थान पर या एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने, ले जाने की अनुमति दी गयी हैं। इसके अलावा, सरकार ने कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स सहित उसकी आपूर्ति श्रृंखला और मरम्मत की दुकानों को खुली रहने की अनुमति दी है। फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी लॉकडाउन के दौरान खुले रहने की अनुमति है। चालू खरीफ फसलों की बुवाई के दौरान खेती के काम में उपयोग होने वाली वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के लिए, सरकार ने उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के विनिर्माण, वितरण और खुदरा कारोबार को अनुमति दी है। लॉकडाउन के दौरान मत्स्यपालन क्षेत्र को नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मछली और मछली उत्पादों, मछली के जरवे और चारा के साथ-साथ इन गतिविधियों में लगे कामगारों को काम करने की अनुमति है। समुद्री और अंतर्देशीय मछली पकड़ने के काम और साथ ही साथ जलीय कृषि उद्योग जिसमें भोजन, रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन शामिल हैं - को काम करने की अनुमति है। हैचरी, फीड प्लांट और वाणिज्यिक एक्वेरिया की भी काम करने की अनुमति है। उपभोक्ताओं को दूध की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और किसानों की सुरक्षा के लिए, सरकार ने दूध और दूध उत्पादों के संग्रह, प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री करने की अनुमति दी है। दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों तक परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित संबंधित कामों की भी अनुमति है। लॉकडाऊन के दौरान पोल्ट्री फार्म और हैचरी के साथ-साथ पशुधन से खेती के कामकाज करने की भी अनुमति है। पशुधन क्षेत्र को पशु आहार की सुचारू आपूर्ति के लिए, सरकार ने मक्का और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति सहित पशुचारा बनाने वाले संयंत्रों को भी काम करने की अनुमति दी है। सरकार ने लॉकडाऊन के दौरान गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों की भी काम करने की अनुमति दी है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले चुकाना होगा बढ़ा हुआ बकाया सरचार्जः CBDT

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आयकर विभाग ने कहा है कि दो करोड़ रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय वाले करदाताओं को इस बार अपना आयकर विवरण जमा कराने से पहले वित्तीय वर्ष 2019-20 के बढ़े हुए सरचार्ज के मुताबिक बकाया कर जमा कराना होगा। यह आदेश उन लोगों के लिए है, जिन्होंने 2019-20 में आय के स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) की गणना करते समय बढ़े हुए सरचार्ज के मुताबिक कर नहीं चुकाया है।

विभाग ने स्पष्ट किया है चूंकि संबंधित वित्त वर्ष का बजट जुलाई में पेश किया गया था। इसमें सरचार्ज की बढ़ी दरें वर्ष के शुरू से लागू मानी गई थी, इसलिए कर दाताओं के इस बकायेे पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ब्याज छूट के लिए शर्त यह है कि करदाता ने पुरानी दर पर टीडीएस/टीसीएस सही काटा हो और उसे सही समय के अंदर जमा करा दिया हो।

वर्ष 2019-20 का बजट पांच जुलाई को प्रस्तुत किया गया था। उसमें दो से पांच करोड़ रुपये के बीच की आय वालों के लिए कर सरचार्ज बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया। इसी तरह पांच करोड़ रुपये से ऊपर की आय वालों पर सरचार्ज की दर 37 प्रतिशत कर दी गई थी। पहले सरचार्ज की दर 15 प्रतिशत थी और बढ़ी दरों को पहली अप्रैल 2019 से लागू माना गया है।

वर्ष 2019 में मई में मोदी सरकार के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद जुलाई में पूर्ण बजट पेश किया गया। वित्त विधेयक जुलाई में पारित हुआ। इससे पहले फरवरी में आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक स्पष्टीकरण में कहा है कि उसे ऐसे कई मामले नजर में आए हैं, जहां करदाताओं ने 1 अप्रैल से 4 जुलाई, 2019 के बीच के लेनदेन पर टीडीएस/ टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रह) की कटौती सरचार्ज की बढ़ी हुई दर से नहीं की है। इस लिए उन्होंने चूक की है। बहरहाल विभाग ने उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ राहत दी है, जिसमें उन्हें डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। बशर्ते कि ऐसे करदाता तय शर्तों के अनुरूप बकाया कर रिटर्न दाखिल करने से पहले चुका दें।

भारत की आर्थिक वृद्धि 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान, कोरोना वायरस से दुनिया मंदी की ओरः मुद्राकोष

वाशिंगटन। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को भारत की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर 2020 में 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। उसने कहा कि कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां ठप होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था भीषण मंदी की ओर बढ़ रही है। यह 1930 में आयी महामंदी के बाद सबसे बड़ी मंदी है।भारत में आर्थिक वृद्धि का यह स्तर रहता है तो यह 1991 में शुरू उदारीकरण के बाद सबसे कम वृद्धि दर होगी। इसके बावजूद मुद्राकोष ने विश्व अर्थव्यवस्था के बारे में अपनी रिपोर्ट के नये संस्करण में भारत को तीव्र वृद्धि वाली उभरती अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में रखा है। भारत उन दो बड़े देशों में शामिल है जहां 2020 में वृद्धि दर सकारात्मक होगी। दूसरा देश चीन है जहां आईएमएफ के अनुसार 1.2 प्रतिशत वृद्धि दर रह सकती है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने ने कहा, ''हमारा अनुमान है कि 2020 में वैश्विक वृद्धि में 3 प्रतिशत की गिरावट आएगी। यह जनवरी 2020 से 6.3 प्रतिशत की गिरावट है। इतने कम समय में बड़ा बदलाव किया गया है।'' उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना वायरस महामारी से सभी क्षेत्रों में वृद्धि दर प्रभावित होगी।उल्लेखनीय है कि दुनिया की महामंदी 1929 में अमेरिका में शुरू हुई। उस समय न्यूयार्क शेयर बाजार में बड़ी गिरावट के साथ निवेशकों को लाखों डॉलर की चपत के बाद इसकी शुरूआत हुई थी।आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों की श्रेणी में ज्यादातर देशों की आर्थिक वृद्धि में गिरावट आएगी। इसमें अमेरिका (-5.9 प्रतिशत), जापान (-5.2 प्रतिशत), ब्रिटेन (-6.5 प्रतिशत), जर्मनी (-7.0 प्रतिशत), फ्रांस (-7.2 प्रतिशत), इटली (-9.1 प्रतिशत) और स्पेन (-8.0 प्रतिशत) गिरावट में रह सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में अच्छी-खासी राजकोषीय मदद के साथ 2020 की शेष अवधि में सुधार आएगा और वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। क्षेत्र की कई अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि दर हल्की होने का अनुमान है। इसमें भारत (1.9 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (0.5 प्रतिशत) शामिल हैं। वहीं थाईलैंड (-6.7 प्रतिशत) समेत कुछ अन्य देशों में आर्थिक वृद्धि में गिरावट की भविष्यवाणी की गयी है। मुद्राकोष के अनुसार दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक वृद्धि में बड़ी गिरावट का अनुमान है। इसमें लातिन अमेरिका (-5.2 प्रतिशत) शामिल हैं। लातिन अमेरिका में ब्राजील में आर्थिक वृद्धि दर में 5.3 प्रतिशत और मेक्सिको में 6.6 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। उभरते और विकासशील यूरोप में वृद्धि दर में 5.2 प्रतिशत की गिरावट जबकि रूस की अर्थव्यवस्था में 5.5 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में वृद्धि दर में 2.8 प्रतिशत की गिरावट आने की आशंका हैं इसमें सऊदी अरब की जीडीपी वृद्धि 2.3 प्रतिशत सिकुड़ सकती है। गोपीनाथ ने कहा कि यह संकट गहरा है और इसके लोगों के जीवन तथा आजीविका पर प्रभाव को लेकर काफी अनिश्चितता है। उन्होंने कहा कि यह काफी हद तक संक्रमण के फैलने, उसे प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने और इसकी दवाएं एवं वैक्सीन विकसित होने पर निर्भर करेगा। इन सभी के बारे में अभी कहना जल्दबाजी होगी। गोपीनाथ ने कहा कि इसके अलावा कई देशों में इस समय स्वास्थ्य संकट के साथ वित्तीय संकट भी हैं जिंसों के दाम लुढ़क गये हैं। उन्होंने कहा कि महामारी 2020 की दूसरी छमाही में हल्की पड़ सकती है और दुनिया भर में कंपनियों के दिवालिया होने और रोजगार बचाने को लेकर जो कदम उठाये जा रहे हैं, उससे 2021 में वैश्विक वृद्धि दर उछलकर 5.8 प्रतिशत हो सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में आर्थिक वृद्धि दर 7.4 प्रतिशत जबकि चीन की 9.2 प्रतिशत रहेगी। वहीं अमेरिका और जापान की जीडीपी वृद्धि दर क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गोपानाथ ने कहा कि यह वास्तव में वैश्विक संकट है क्योंकि कोई भी देश इससे अछूता नहीं है।

इकॉनमी पर अदृश्य वार कर रहा कोरोना वायरसः RBI

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास का मानना है कि घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रकोप से पड़ने वाले प्रभावों से बचाने के लिए सभी तरह के प्रयासों की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के दौरान दास ने कहा कि मैक्रो-इकॉनमी पर इसके बहुत अधिक प्रभाव से पहले इसके प्रसार को रोकने की जरूरत है। इन परिस्थितियों में विभिन्न क्षेत्रों में वित्त के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करना अनिवार्य है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दास ने बैठक के दौरान कोरोना महामारी को 'अदृश्य रूप से वार करने वाला' करार दिया। उन्होंने कहा कि इस महामारी पर जल्द-से-जल्द काबू पाए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हम एक असाधारण समय से गुजर रहे हैं और वर्तमान में देश के सामने जो स्थिति है, वह अभूतपूर्व है। इसलिए घरेलू अर्थव्यवस्था को महामारी के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना अनिवार्य है।' उन्होंने कहा कि यह सुकून देने वाला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के मैक्रो-इकॉनमी (वृहद आर्थिक बुनियादी ढांचे) में निरंतर सुधार हो रहा है, खासकर वैश्विक वित्तीय संकट के बाद की स्थितियों को देखें तो इसमें सुधार है। इस दौरान दास ने 24, 26 और 27 मार्च को हुई बैठक के दौरान 75 आधार अंकों की कटौती पर भी अपनी सहमति जताई। दास ने कहा कि रिजर्व बैंक नजर बनाए हुए है और वह कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता कायम करने के लिए किसी भी तरह के पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कदम उठाने से नहीं हिचकेगा।

अंबेडकर जयंती पर विशेष

बाबा साहेब के 20 अमूल्य विचार

भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वे भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाजसुधारक थे। अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।

- उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को प्रभावित कर सकती है।
- यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए।
- जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है।
- यदि मुझे लगेगा की संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मै इस संविधान को ही जलाऊंगा।
- मैं ऐसे धर्म को मानता हूं, जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए।
- हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं।
- भाग्य में विश्वास रखने के बजाए अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए।
- बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए।
- जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है, वो आपके किसी काम की नहीं।
- जीवन लंबा होने की बजाए महान होना चाहिए।
- एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए।
- समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा।
- हिन्दू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है।
- एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है।
- पति-पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए।
- कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए।
- समाज में अनपढ़ लोग है ये हमारे समाज की समस्या नहीं है लेकिन जब समाज के पढ़े-लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते है और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते है यही हमारे समाज की समस्या है।
- कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए।
- समाज में अनपढ़ लोग है ये हमारे समाज की समस्या नहीं है लेकिन जब समाज के पढ़े-लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते है और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते है यही हमारे समाज की समस्या है।
- हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत कि 'एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता' को दोहराता है उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता।
- इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है, जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो।
- मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर हैं। एक विचार को प्रचार-प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं।

क्या होती है सप्तपदी

जानिए 7 वचनों का महत्व

हिन्दू धर्म में विवाह के दौरान सात फेरे लिए जाते हैं जिन्हें सप्तपदी कहते हैं। सप्तपदी के सात वचन होते हैं जिन्हें वर और वधु को निभाना होता है। कन्या यह वचन अपने होने वाले पति से मांगती है। यह सात वचन दाम्पत्य जीवन को खुशहाल और सफल बनाने हेतु होते हैं। अधिकतर लोग विवाह के बाद इन सात वचनों को भूल जाते हैं इसलिए उनके दाम्पत्य जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। यदि पति और पत्नी इन वचनों के महत्व को समझे तो जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आओ जानते हैं इन 7 वचनों का महत्व।

सात पग : सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय, आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवां पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन-सहन के लिए, अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवनपर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है।

पहला वचन :

तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञकर्म मया
सहैव प्रियवयं कुर्याः
वामांगमायामि तदा त्वदीयं
ब्रवीति वाक्यं प्रथमं कुमारी!।

अर्थात : कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थयात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत-उपवास अथवा अन्य धर्म कर्म का कोई कार्य करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं।

दूसरा वचन :

पुज्यो यथा स्वौ पितरौ ममापि
तथेशभक्तो निजकर्म कुर्याः
वामांगमायामि तदा त्वदीयं
ब्रवीति कन्या वचनं द्वितीयम!!

अर्थात : कन्या अपने दूसरे वचन में वर मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता-पिता का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार मेरे माता-पिता का भी सम्मान करें तथा कुटुम्ब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने रहें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं।

तीसरा वचन :

जीवनम अवस्थात्रये पालनां कुर्यात
वामांगंयामितदा त्वदीयं ब्रवीति
कन्या वचनं तृतीयं!!

अर्थात : तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूं।

चौथा वचन :

कुटुम्बसंपालनसर्वकार्य कर्तु
प्रतिज्ञां यदि कातं कुर्याः
वामांगमायामि तदा त्वदीयं
ब्रवीति कन्या वचनं चतुर्थः॥

अर्थात : कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर-परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जब कि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व आपके कंधों पर है। यदि आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूं।

पांचवां वचन :

स्वसद्यकार्ये व्यहारकर्मण्ये
व्यये मामापि मन्त्रयेथा
वामांगमायामि तदा त्वदीयं
ब्रूते वचः पंचमत्र कन्या!!

अर्थात : पांचवें वचन में कन्या वर मांगती है कि जो वह कहती है, वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। वह कहती है कि अपने घर के कार्यों में, लेन-देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं।

छठवां वचन :

न मेपमानमं सविधे सखीना
द्यूतं न वा दुर्व्यसनं भंजश्चेत
वामाम्गमायामि तदा त्वदीयं
ब्रवीति कन्या वचनं च षष्ठम!!

अर्थात : कन्या अपने छठे वचन में कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूं, तब आप वहां सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आपको दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं।

सातवां वचन :

परस्त्रियं मातूसमां समीक्ष्य
स्नेहं सदा चेन्मयि कान्त कूर्या।
वामांगमायामि तदा त्वदीयं
बूते वचः सप्तमंत्र कन्या!!

अर्थात : कन्या अपने अंतिम वचन के रूप में वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता के समान समझेंगे और पति-पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन मुझे दें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूं।

सप्तपदी का महत्व : विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों या शरीर के गहनतम रूपों तक तादात्म्य बिठाने करने का विधान रचा जाता है। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक-दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवनपर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का भी महत्व है। 'मैत्री सप्तपदीन मुच्यते' अर्थात एकसाथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही दो अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है अतः जीवनभर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पग में वर, कन्या से कहता है कि 'हम दोनों 7 पद चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं।' मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति-पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एकसाथ उठे इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम साथ-साथ 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवनपर्यंत पालन करते हुए एक-दूसरे के प्रति सदैव एकनिष्ठ रहें और पति-पत्नी के रूप में जीवनपर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे तथा हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो।

विवाह एक संस्कार : हिन्दू धर्म में विवाह को पाणिग्रहण संस्कार कहते हैं। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन हिन्दू धर्म में विवाह बहुत ही भली-भांति सोच- समझकर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिन्दू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है।

सात फेरे या सप्तपदी : हिन्दू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते, तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। न एक फेरा कम, न एक ज्यादा। इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं जिसे 'सप्तपदी' भी कहा जाता है। ये सातों फेरे या पद 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है जिसे पति-पत्नी जीवनभर साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिन्दू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर दो तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं।

सात फेरे ही क्यों : भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत विशिष्ट मानी गई है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, सप्त लोक, 7 चक्र, सूर्य के 7 घोड़े, सप्त रश्मि, सप्त धातु, सप्त पुरी, 7 तारे, सप्त द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा, आदि का उल्लेख किया जाता रहा है। यही सभी ध्यान रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है जिसे 'सप्तपदी' कहा गया है।

कोरोना वायरस महामारी के चलते यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री मार्च में 51 प्रतिशत गिरी : सियाम

नयी दिल्ली। एजेंसी

यात्री वाहनों की बिक्री मार्च में 51 प्रतिशत गिर गयी। कोरोना वायरस महामारी के सामुदायिक फैलाव को रोकने के लिए देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन (सार्वजनिक पाबंदी) किया गया है।वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) ने कहा कि मार्च में यात्री वाहनों की बिक्री 1,43,014 वाहन रही। यह पिछले साल मार्च के 2,91,861 वाहनों की बिक्री के मुकाबले 51 प्रतिशत कम है। इसी तरह वाणिज्यि वाहनों की बिक्री अवधि में 88.95 प्रतिशत घटकर 13,027 वाहन रही जो इससे पिछले साल मार्च में 1,09,022 वाहन थी।दोपहिया वाहनों की बिक्री भी मार्च में गिरी है। समीक्षावधि में इसकी कुल 8,66,849 इकाइयां बिकीं जो मार्च 2019 की 14,40,593 इकाइयों के मुकाबले 39.83 प्रतिशत कम है।सभी श्रेणियों के वाहनों की बिक्री समीक्षावधि में 44.95 प्रतिशत घटकर 10,50,367 वाहन रही। मार्च 2019 में यह आंकड़ा 19,08,097 वाहन था।सियाम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, ''मार्च का महीना सभी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय में से एक रहा है। सार्वजनिक पाबंदी की वजह से पिछले हफ्तों में वाहनों की बिक्री और उत्पादन बिल्कुल ठप सा रहा है।''उन्होंने कहा कि मूल कलपुर्जा विनिर्माता (ओईएम) कंपनियों को भी अपनी लागत और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल आ रही है।वढेरा ने कहा, ''सियाम के अनुमान के अनुसार सार्वजनिक पाबंदी के चलते कारखाने बंद रहने के प्रत्येक दिन पर वाहन उद्योग के 2,300 करोड़ रुपये के कारोबार का नुकसान हो रहा है।''उन्होंने कहा कि वाहन उद्योग सरकार के साथ बातचीत कर रही है कि किस तरह कोरोना वायरस से पैदा हुई मुश्किलों का उद्योग पर न्यूनतम असर हो, विशेषकर घरेलू वाहन उद्योग को।वढेरा ने कहा, '' वाहन उद्योग को आपूर्ति, मांग और वित्त की उपलब्धता जैसे तीनों प्रमुख मुद्दों की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र में वृद्धि को वापस पटरी पर लाने के लिए यह तीनों ही अहम हैं।''बीते वित्त वर्ष एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच यात्री वाहनों की बिक्री में 17.82 प्रतिशत की गिरावट देखी गयी। समीक्षावधि में कुल 27,75,679 यात्री वाहन बिके जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में कुल 33,77,389 यात्री वाहनों की बिक्री हुई थी। इसी तरह वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री 28.75 प्रतिशत टूटकर 7,17,688 वाहन रही। जबकि दोपहिया वाहनों की बिक्री 17.76 प्रतिशत घटकर 1,74,17,616 वाहन रही। समीक्षावधि में सभी श्रेणियों में कुल वाहन बिक्री 17.96 प्रतिशत घटकर 2,15,48,494 वाहन रही। इससे पिछले वित्त वर्ष 2018-19 में यह संख्या 2,62,66,179 वाहन थी।

गडकरी की एमएसएमई उद्योग के साथ बैठक, मदद का भरोसा दिलाया

नागपुर। एजेंसी

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एमएसएमई उद्योग के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। बैठक में गडकरी ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन (बंद) के मद्देनजर एमएसएमई उद्योग के समक्ष आ रही चुनौतियों पर चर्चा की और मदद का भरोसा दिलाया। एमएसएमई मंत्री ने नागपुर में अपने निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अखिल भारतीय प्लास्टिक विनिर्माता संघ (एआईपीएमए) और पीएचडी चैंबर आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की। बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने मंत्री के समक्ष उद्योग की कुछ चिंताओं को रखा और साथ ही सुझाव भी दिए। उद्योग के प्रतिनिधिनियों ने गडकरी को बिजली और पानी के बिलों में निश्चित शुल्क को माफ करने, कुछ भुगतान के लिए रोक की अवधि बढ़ाने, कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं में शामिल करने, बंद के दौरान कर्मचारियों के वेतन का भुगतान उनके ईएसआई और भविष्य निधि से करने, सब्सिडी के जरिये नकदी संकट को हल करने, जीएसटी भुगतान के लिए विस्तार और वस्तुओं के निर्यात के लिए परिवहन में राहत जैसे उपायों के सुझाव दिए। गडकरी ने उद्योग के प्रतिनिधिनियों के सुझाव सुनने के बाद उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इन मुद्दों को वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष रखेंगे। मंत्री ने कहा, ''मेरे विभाग से संबंधित मुद्दों को तत्काल हल किया जाएगा। हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उद्योग को अन्य अंशधारकों मसलन बैंक, वित्तीय संस्थानों और बिजली क्षेत्र की स्थिति को भी देखना चाहिए। वे भी दबाव में हैं और उन्हें भी हमारे समर्थन की जरूरत है।'' गडकरी ने कहा कि उद्योग को मिलकर काम करना चाहिए और कोविड-19 संकट समाप्त होने के बाद उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।

नरम मांग से कच्चे तेल का वायदा 11.4 प्रतिशत गिरा

नयी दिल्ली। एजेंसी

हाजिर बाजार में नरम मांग के कारण कारोबारियों के सौदे घटाने से बुधवार को वायदा कारोबार में कच्चा तेल 11.4 प्रतिशत गिरकर 1,577 रुपये प्रति बैरल पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल डिलिवरी वाले कच्चे तेल की कीमत 203 रुपये यानी 11.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,577 रुपये प्रति बैरल रह गई। इसमें 29,934 लॉट के लिए कारोबार हुआ। इसी तरह मई डिलिवरी के लिए कच्चे तेल की कीमत 144 रुपये यानी 6.41 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,102 रुपये प्रति बैरल रह गई। इसमें 4,160 लॉट के लिए कारोबार हुआ। बाजार विश्लेषकों ने कहा कि कच्चे तेल की वायदा कीमतों में गिरावट आने का मुख्य कारण कमजोर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करना रहा। हालांकि, वैश्विक स्तर पर न्यूयार्क में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 0.05 प्रतिशत बढ़कर 20.12 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। ब्रेंट क्रूड 1.45 प्रतिशत गिरकर 29.17 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

लॉकडाउन की बढ़ी अवधि में चलता रहेगा बैंक, बीमा का काम: सरकार

नयी दिल्ली। एजेंसी

सरकार ने लॉकडाउन (बंद) की बढ़ी अवधि के लिये नये दिशानिर्देश जारी करते हुए बुधवार को कहा कि बैंक और बीमा जैसी महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं से जुड़े काम पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार ने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये पिछले महीने 25 मार्च को 21 दिन के बंद की घोषणा की थी, जिसकी समयसीमा 14 अप्रैल को समाप्त हो गयी। इस दौरान बैंकिंग व बीमा से संबंधित कार्यों को जारी रहने की छूट दी गयी थी। सरकार ने बंद को अब तीन मई तक के लिये बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने नये दिशानिर्देशों में कहा, ''उद्योग जगत को पर्याप्त नकदी तथा ऋण सहायता मुहैया कराते रहने के लिये रिजर्व बैंक, बैंक, एटीएम, बीमा कंपनियां तथा सेबी द्वारा अधिसूचित पूंजी व बांड बाजार खुले रहेंगे।'' बैंकिंग परिचालन की मदद करने वाले सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सेवा प्रदाता, बैंकिंग प्रतिनिधि और एटीएम परिचालन तथा नकदी का प्रबंधन देखने वाली कंपनियां भी काम करती रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि जब तक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तब तक बैंकों की शाखाएं सामान्य समय के हिसाब से काम करती रहेंगी। स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करायेगा। बैंक कर्मियों को खाताधारकों के बीच आपस में दूरी तथा भीड़ होने से रोकने में भी स्थानीय प्रशासन मदद मुहैया कराएगा। मंत्रालय ने कहा कि सेवा क्षेत्र के साथ ही राष्ट्रीय वृद्धि के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है। इस लिहाज से ई-वाणिज्य कंपनियां, आईटी व इससे संबद्ध परिचालन, सरकारी गतिविधियों से जुड़े डेटा व कॉल सेंटर, ऑनलाइन अध्ययन-अध्यापन आदि को भी छूट रहेगी।

कोरोना: गुजरात की ये तीन दवा कंपनियां करेंगी 'वंडर ड्रग' हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का दोगुना उत्पादन

नयी दिल्ली। एजेंसी

कोरोना के मामले भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक 11 हजार से ज्यादा लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 345 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। दवा की बात करें तो अभी हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) की जबर्दस्त डिमांड है। गुजरात की तीन दवा कंपनी- जायडस कैडिला, वाइटल फार्मा और मंगलम ड्रग्स ऐंड ऑर्गेनिक्स अगले महीने से हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन बनाने के लिए जरूरी ऐक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट (API) का डबल उत्पादन करेगी। अभी 20 करोड़ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का उत्पादनवर्तमान में देश में 40 टन एपीआई की मदद से 20 करोड़ हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन यूनिट दवा तैयार की जाती है। इन तीन कंपनियों का लक्ष्य अगले महीने तक एपीआई उत्पादन को 80 टन पहुंचाने का है, जिससे 40 करोड़ यूनिट हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा तैयार की जा सके।

35.8 लाख हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट अमेरिका को निर्यात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मदद मांगे जाने के बाद भारत अमेरिका को 35.8 लाख टैबलेट हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन और 9 टन एपीआई का निर्यात कर चुका है। पहले भारत ने एपीआई के निर्यात पर रोक लगा दिया था, बाद में ट्रंप ने फोन कर पीएम मोदी से मदद मांगी और सरकार ने आंशिक निर्यात की छूट दी है।

नए सिम के 'एक्टिवेशन' पर सरकार जल्द करेगी फैसला : सीओएआई

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

दूरसंचार उद्योग के संगठन सीओएआई ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के दौरान सिम कार्ड के 'एक्टिवेशन' पर सरकार जल्द फैसला करेगी। इस संदर्भ में प्रक्रिया तय करने के लिए सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। भारतीय सेल्युलर परिचालक संघ (सीओएआई) के महानिदेशक राजन मैथ्यूज ने कहा कि सरकार के सहयोग से उद्योग नेटवर्क संबंधी मुद्दों को हल करने में सक्षम है। मैथ्यूज ने कहा, ''डीओटी (दूरसंचार विभाग) सुरक्षा से संबंधित मुद्दों की समीक्षा करने के बाद सिम के एक्टिवेशन पर फैसला करेगा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सिम को लोगों के घर तक पहुंचान होगा।'' सीओएआई ने कहा कि डीओटी सचिव अंशु प्रकाश ने जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग की तैयारियों की समीक्षा की और नेटवर्क से संबंधित मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया। उद्योग संगठन के अनुसार डीओटी ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के भुगतान से जीएसटी हटाने का आश्वासन दिया है। उद्योग ने लाइसेंस फीस, एसयूसी और नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के भुगतान पर जीएसटी की छूट का भी आग्रह किया है।

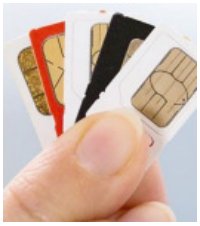

आईएमएफ का सभी देशों से चिकित्सा आपूर्ति के निर्यात पर अंकुश नहीं लगाने का आह्वान

वाशिंगटन। एजेंसी

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) ने सभी देशों से चिकित्सा आपूर्ति के निर्यात पर अंकुश नहीं लगाने का आह्वान किया है। दुनियाभर में फैली कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस समय चिकित्सा सामान की बहुत अधिक जरूरत है। ऐसे में आईएमएफ ने सभी देशों से कहा है कि वे अपने यहां से चिकित्सा सामग्री के निर्यात पर किसी तरह का अंकुश लगाने से बचें। अब तक दुनियाभर में इस महामारी से 1,19,000 लोगों की जान गई है और करीब 20 लाख लोग इससे संक्रमित हैं। कोरोना वायरस की वजह से वैश्विक स्तर पर सर्जिकल मास्क, गाउन और वेंटिलेटरों की भारी मात्रा में जरूरत है। भारतीय-अमेरिकी मूल की आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम सभी देशों का आह्वान करते हैं कि वे चिकित्सा आपूर्ति पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाएं। यह इस समय बेहद जरूरी है। आप जानते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वैश्विक सहयोग बेहद जरूरी है। यह चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक सामान के व्यापार पर अंकुश लगाने का उचित समय नहीं है।'' आईएमएफ और विश्वबैंक की बैठक के पहले मुद्राकोष मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में गोपीनाथ ने कहा कि वैश्वीकरण की दृष्टि से यह इस महामारी से निपटने के लिए एक मुश्किल समय है। उन्होंने कहा कि लोगों की यात्रा पर अंकुश है। लोग काम पर नहीं जा सकते। कारखाने बंद हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला टूट चुकी है। इस संकट की वजह से ऐसा हुआ है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैश्वीकरण से हमें जो लाभ मिला है, हम उसे गंवाएं नहीं। सीएनएन की खबर के अनुसार चिकित्सा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न देश निर्यात पर अंकुश लगा रहे हैं। छह मार्च को इटली की एकमात्र वेंटिलेटर उत्पादक सियरे इंजीनियरिंग ने कहा था कि सरकार के निर्देश पर वह अपना सारा उत्पादन घरेलू इस्तेमाल के लिए रख रही है। यूरोपीय संघ ने भी 15 मार्च को फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क और गाउन जैसे उत्पादों के निर्यात पर अंकुश लगाने की घोषणा की थी।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने कर्नाटक मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में योगदान किया

बैंगलोर। आईपीटी नेटवर्क

कोविड-19 के हमले से पैदा हुए संकट का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (टीकेएम) ने आज कर्नाटक मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में योगदान किया। यह योगदान कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण (केएसडीएमए) को महामारी से प्रभावित जीवन के पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है ताकि राज्य में लोगों के जीवन को सामान्य बनाया जा सके। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक श्री शेखर विश्वनाथन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राजू बी केटकले और कर्मचारी यूनियन के सचिव श्री दीपक कुमार ने कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बीएस येदुरप्पा को रुपए 2,00,00,000/- (दो करोड़ रुपए) का एक चेक दिया।

इस पूरी राशि में रुपए 1,3548,553 टीकेएम ने दिए हैं जो कर्नाटक राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण (केएसडीएमए) को दिया गया जबकि बाकी रुपए 64,51,447 की राशि कर्मचारियों से एकत्र की गई है और कर्नाटक मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड-19 में दी गई है।

इस बारे में बताते हुए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के वाइस चेयरमैन और पूर्णकालिक निदेशक श्री शेखर विश्वनाथनने कहा, 'संकट के इस समय में टोयोटा भिन्न समुदायों के समर्थन में पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मानवता को बेजोड़ संकट में डालने वाली इस महामारी से निपटने के लिए हर तरह की सहायता करने के लिए तैयार है। केंद्र और राज्य – दोनों सरकारों ने कोविड-19 को ज्यादा फैलने से रोकने के लिए मजबूत, निर्णायक और बेहद सक्रियता वाले निर्णय लिए हैं। हम उनके भारी प्रयासों का पूरा समर्थन करते हैं और प्रार्थना करते हैं देश में लोगों का जीवन तेजी से सामान्य होने की ओर बढ़े।'

इसके अलावा, टोयोटा समूह की कंपनियों ने भी कर्नाटक राज्य सरकार को रुपए 55,00,000 की राशि दान दी है। महामारी की शुरुआत होने के बाद से टीकेएम तेजी से बदलती स्थिति पर नजर रख रही है और सक्रियता से उपयुक्त कार्रवाई कर रही है और यह समाज की आवश्यकता के अनुसार होता है। समाज की सहायता करने में कंपनी हमेशा अग्रणी रही है और समाज से संबंधित अहम मामलों में यह सरकार के साथ रहती है। इस समय चल रहे संकट से निपटने के लिए कंपनी ने अपने कई सारे स्टेकधारकों के साथ कई तरह की कार्रवाई की है। हाल में कर्नाटक के सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 3000 हजमत सूट सौंपे गए थे। इसी तरह दिहाड़ी मजदूरों को आवश्यक वस्तुओं के 1000किट और 5000 से ज्यादा लोगों को सैनिटाइजर, मास्क आदि दिए गए तो पुलिस विभाग के हैं। इसके अलावा राज्य के स्वास्थ्य विभाग की सहायता के लिए 14 बसें लगाई गई हैं। टीकेएम ने अपने आपूर्तिकर्ता साझेदार स्टम्प श्युले एंड सोमप्पा स्प्रिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का भी समर्थन किया है ताकि हेल्थकेयर वर्कर्स के लिए 'फेस शील्ड्स' का उत्पादन बढ़ाया जा सके और 275 से 10000 यूनिट रोज किया जा सके।

ईएसआई योजना के अंशदान जमा कराने की समयसीमा को 15 मई तक बढ़ी

नयी दिल्ली। एजेंसी

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन (रोक) के मद्देनजर फरवरी माह के लिए ईएसआई के अंशदानों का जमा कराने की समयसीमा को 15 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले फरवरी और मार्च के अंशदान भरने की तारीख को क्रमशः 15 अप्रैल और 15 मई तक बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशव्यापी लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया। ईएसआई योगदान दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने के कारणों के बारे में श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कई प्रतिष्ठान अस्थायी रूप से बंद हैं और कोविड-19 संकट के कारण लागू पाबंदियों के चलते श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं। ईएसआई योगदान दाखिल करने की विस्तारित अवधि के दौरान प्रतिष्ठानों से कोई जुर्माना या ब्याज नहीं लगाया जाएगा। इस फैसले से 3.49 करोड़ बीमित व्यक्तियों (आईपी) और 12,11,174 नियोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसके अलावा ईएसआईसी ने लाभार्थियों के लिए कुछ अन्य राहत उपाय भी किए हैं।

कोरोना संकट में 52 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकता है सोने का दाम

सोने में निवेश पहुंचा सकता है लाभ

इंदौर। सराफा व्यवसायी संतोष वाधवानी (रत्न विशेषज्ञ) ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सोने की नई कीमत रूपए 46500 पहुंच चुकी है वहीं चांदी के भाव रूपए 44000 तक पहुंच गयी हैं। संतोष

वाधवानी ने संभावना व्यक्त की है कि कोरोना संकट के चलते सोने चांदी जैसी कीमती धातु की कीमतें बढ़ेगी और आगामी भविष्य में सोना प्रति 52 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं का व्यापार बुलियन मार्केट के जरिए ही होता है ।

कोविड-19 से लड़ने के लिए टैफे ग्रुप ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रुपये का योगदान दिया

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

टैफेग्रुप - ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, आयशर और मैसी फर्ग्यूसन ट्रैक्टर के निर्माता ने कोविड-19 के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार की लड़ाई में सहयोग देते हुए मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष में 2 करोड़ रूपये का दान दिया है। लॉकडाउन के बाद से, टैफे ग्रुप की विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां अपने संचालन क्षेत्र के नज़दीकी इलाकों में कानून व्यवस्था की देखरेख कर रहे अधिकारियों, स्वच्छता कर्मचारियों, स्थानीय गरीब लोगों और प्रवासी श्रमिकों को भोजन, चिकित्सा सुविधा और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों का वितरण कर रही हैं।रबी के मौसम के दौरान कोरोना वायरस के प्रकोप से छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, और इस संकट को दूर करने के प्रयास में उनकी सहायता करने की दृष्टि से टैफे ने चुनिंदा राज्यों में एक अनूठी मुफ्त ट्रैक्टर रेंटल योजना भी शुरू की है।

TAFE
Tractors and Farm Equipment Limited

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।